भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*252

दिनांक 13 मार्च, 2018 को उत्तर दिया गया

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार

***252. श्री सतीश चंद्र दुबे:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2024 तक उक्त क्षेत्र में रोजगार सृजन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के बारे में दिनांक 13 मार्च, 2018 को लोक सभा में उत्तरित तारांकित प्रश्न सं.252* के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क): केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कराए गए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 तक पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्रमश: 16.87 लाख, 17.41 लाख और 17.73 लाख है । वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 तक नियोजित व्यक्तियों की राज्य-वार संचयी संख्या **संलग्नक** में दी गई है ।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संपूर्ण संवर्धन एवं विकास के लिए और 14वें वित्त आयोग के चक्र की सह-समाप्ति वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटन से क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु **प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई)** के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की विभिन्न स्कीमें चलाता रहा है । पीएमकेएसवाई में इस अवधि के दौरान स्कीम के अंतर्गत 5,30,500 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन की परिकल्पना की गई है । सरकार ने क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए खाद्य उत्पादों के निर्माण में स्वत: अनुमोदन के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा भारत में उत्पादित और/अथवा निर्मित खाद्य उत्पादों के बारे में ई-वाणिज्य के माध्यम से व्यापार सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने, वहनीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2,000 करोड़ रुपए के विशेष कोष की स्थापना करने, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) के लिए कृषि कार्यकलाप के रूप में खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण यूनिटों तथा शीत श्रृंखला का वर्गीकरण करने, अधिकांश खाद्य उत्पादों के लिए वस्तु एवं सेवाएँ कर (जीएसटी) की दरें कम करने, नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों इत्यादि के लिए लाभ पर आयकर से 100% छूट देने जैसे अनेक नीतिगत उपाय किए हैं।

******

संलग्नक

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के बारे में दिनांक 13 मार्च, 2018 को लोक सभा में उत्तरित तारांकित प्रश्न सं.252* के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

अलग-अलग वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नियोजित कुल व्यक्तियों की राज्य-वार अनुमानित संख्या				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
1	अंडमान और निकोगार द्वीप समूह	129	127	116
2	आंध्र प्रदेश	144395	139067	152848
3	अरूणाचल प्रदेश	लागू नहीं	लागू नहीं	1375
4	असम	79141	88449	87970
5	बिहार	23930	22406	35881
6	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	348	1008	903
7	छत्तीसगढ़	22058	23052	25427
8	दादरा और नगर हवेली	220	222	295
9	दमन और दीव	1837	1810	2820
10	दिल्ली	10923	13841	13735
11	गोवा	6242	6936	7299
12	गुजरात	90319	100025	97624
13	हरियाणा	48767	41879	49518
14	हिमाचल प्रदेश	15734	13237	11919
15	जम्मू और कश्मीर	7459	9102	7501
16	झारखंड	5143	4736	6470
17	कर्नाटक	110188	108406	113143
18	केरल	163768	158000	153853
19	मध्य प्रदेश	36091	40134	45977
20	महाराष्ट्र	217124	234197	239344
21	मणिपुर	565	433	536
22	मेघालय	635	749	868
23	नागालैंड	99	135	267
24	ओडिशा	35374	27170	27225
25	पुदुच्चेरी	3945	4610	5023
26	पंजाब	90814	104003	106618
27	राजस्थान	40399	37530	39641
28	सिक्किम	1668	1843	1670
29	तमिलनाडु	188707	194331	204648
30	तेलंगाना	70364	79191	60315
31	त्रिपुरा	1555	1547	1998
32	उत्तर प्रदेश	160326	166327	158491
33	उत्तराखंड	26655	30344	28381
34	पश्चिम बंगाल	81858	85966	83656
	कुल	***1686780***	***1740813***	***1773355***
स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण 2014-15				